IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, March 2026
Impact Factor: 8.2

मनरेगा में भुगतान सुधार और समय पर मजदूरी तथा निजी क्षेत्र की कमाई पर प्रभाव: रीवा क्षेत्र का अध्ययन

रोहित सिंह

अतिथि विद्वान - वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश (Abstract)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में भुगतान प्रणाली के सुधार, विशेष रूप से बायोमेट्रिक और आधार लिंकेज (Aadhaar Based Payment System - ABPS) के माध्यम से, ग्रामीण मजदूरों को समय पर मजदूरी सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा गया है। यह अध्ययन मध्य प्रदेश के रीवा जिले को केंद्र में रखकर ABPS के प्रभाव का विश्लेषण करता है।

प्राथमिक रूप से द्वितीयक डेटा (nrega.nic.in से रीवा जिले के 2024-25 व्यय रिपोर्ट, विलंबित भुगतान रिपोर्ट) और साहित्य समीक्षा पर आधारित यह शोध दर्शाता है कि जनवरी 2024 से ABPS अनिवार्य होने के बाद आधार सीडिंग 99.49% पहुंच गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। हालांकि, समय पर मजदूरी में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखा (The Hindu अध्ययन 2025 के अनुसार, ABPS में 39% भुगतान 7 दिनों में जबकि सामान्य खाते में 36%)। रीवा में 2024-25 में कुल व्यय ₹10,394.33 लाख रहा, जिसमें अकुशल मजदूरी प्रमुख थी, लेकिन विलंबित भुगतान अभी भी बने हुए हैं।

निजी क्षेत्र की कमाई पर प्रभाव सकारात्मक रहा – मनरेगा की समयबद्ध मजदूरी ने ग्रामीण मजदूरी दर बढ़ाई, जिससे निजी नियोक्ताओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। रीवा जैसे क्षेत्र में यह प्रवासन कम

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 3, March 2026 Impact Factor: 8.2

करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ। अध्ययन नीतिगत सुझाव देता है कि फंडिंग की कमी दूर कर ABPS को और प्रभावी बनाया जाए।

कीवर्ड्स (Keywords): मनरेगा, ABPS, आधार लिंकेज, समय पर मजदूरी, निजी क्षेत्र की कमाई, रीवा जिला, ग्रामीण विकास, DBT, बायोमेट्रिक भुगतान।

परिचय (Introduction)

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा 2005 से एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना रही है। यह 100 दिनों का गारंटीड रोजगार प्रदान करती है और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का प्रमुख साधन है। लेकिन शुरू के वर्षों में भुगतान विलंब, लीकेज और बैंक खाता समस्याओं के कारण योजना की प्रभावशीलता प्रभावित होती रही। जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने Aadhaar Payment Bridge System (APBS) को अनिवार्य कर दिया, जो Direct Benefit Transfer (DBT) के साथ आधार लिंकेज पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक खाता बदलने की समस्याओं को हल करना और समय पर मजदूरी सुनिश्चित करना था। PIB (18 मार्च 2025) के अनुसार, 13.55 करोड़ सक्रिय मजदूरों में आधार सीडिंग 99.49% हो चुकी है। मध्य प्रदेश में औसत दैनिक मजदूरी ₹228.77 (2024-25) है। रीवा जिला मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, जहां कृषि और मजदूरी मुख्य आजीविका हैं। यहां मनरेगा की मांग अधिक है, लेकिन भुगतान विलंब से मजदूर प्रभावित होते हैं।

यह अध्ययन निम्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है:

- ABPS ने रीवा में समय पर मजदूरी को कितना सुधारा?
- इसका निजी क्षेत्र की मजदूरी दरों पर क्या प्रभाव पड़ा?

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, March 2026
Impact Factor: 8.2

साहित्य में Sukhtankar (2016) और Patwardhan & Tasciotti (2022) ने मनरेगा के मजदूरी दर बढ़ाने का उल्लेख किया है। लेकिन ABPS के बाद के प्रभाव पर Lib Tech India का 2025 अध्ययन (Indian Journal of Labour Economics) कहता है कि ABPS से समय पर भुगतान में कोई बड़ा अंतर नहीं आया – मुख्य समस्या फंड की कमी है।

रीवा में 2024-25 का कुल व्यय ₹10,394.33 लाख था (अकुशल मजदूरी ₹5,091.43 लाख)। यह अध्ययन द्वितीयक डेटा पर आधारित है और रीवा को केस स्टडी के रूप में लेता है। यह शोध ग्रामीण नीति निर्माण में सहायक होगा।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन मिश्रित पद्धति पर आधारित है, लेकिन मुख्य रूप से द्वितीयक डेटा विश्लेषण का उपयोग किया गया है क्योंकि प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए संसाधन सीमित थे।

1. डेटा स्रोत:

- आधिकारिक: nrega.nic.in और mnregaweb4.nic.in से रीवा जिले की MIS रिपोर्ट (2023-24 vs 2024-25) – कुल व्यय, विलंबित भुगतान विवरण, व्यक्ति-दिन।
- PIB.gov.in (मार्च 2025) – ABPS कार्यान्वयन और प्रभाव।
- The Hindu (जनवरी 2025) और अन्य जर्नल (Indian Journal of Labour Economics) – ABPS अध्ययन।
- NSSO और पुराने शोध पत्र (Sukhtankar 2016, Pandey 2018) – निजी क्षेत्र प्रभाव।

2. नमूना: रीवा जिले के 5 ब्लॉक्स (रीवा, हनुमाना आदि) को कवर किया गया। 2024-25 डेटा से तुलना पूर्व-ABPS (2023) से।

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429

Volume 6, Issue 3, March 2026

Impact Factor: 8.2

3. **विश्लेषण तकनीक**:

तुलनात्मक विश्लेषण (Pre-post ABPS)।

प्रतिशत गणना: **आधार सीडिंग** %, **विलंबित भुगतान** %, **मजदूरी दर वृद्धि।**

गुणात्मक: **साहित्य से निजी क्षेत्र प्रभाव (मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरी** 10-20% **बढ़ाई – अध्ययन अनुसार)।**

4. **सीमाएं**: **द्वितीयक डेटा पर निर्भरता, प्राथमिक सर्वे** (200 **मजदूरों का) नहीं किया गया। भविष्य में फील्ड सर्वे (प्रश्नावली**: **भुगतान समय, निजी कमाई पर प्रभाव) जोड़ा जा सकता है।**

5. **नैतिकता**: **सभी डेटा सार्वजनिक स्रोत से, कोई गोपनीयता उल्लंघन नहीं।**

- **समय पर मजदूरी**: ABPS **के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता बढ़ी, लेकिन रीवा में विलंबित भुगतान रिपोर्ट अभी भी उपलब्ध** (nrega.nic.in)। The Hindu **अध्ययन से**: ABPS **और सामान्य खाते में अंतर नगण्य। मुख्य कारण – फंड रिलीज की देरी। रीवा में** 2024-25 **में मजदूरी दर** ₹228+ **रही।**
- **निजी क्षेत्र प्रभाव**: **मनरेगा की समयबद्ध मजदूरी ने निजी मजदूरी दर बढ़ाई** (Pandey 2018 **अध्ययन**: RPC **सर्वे से** 2001-11 **में वृद्धि)। रीवा में कृषि मजदूरों को बेहतर विकल्प मिला, जिससे नियोक्ता मजदूरी बढ़ाने को मजबूर हुए। ऋण कम हुआ** (Patwardhan 2022)।

निष्कर्ष (Conclusion)

ABPS **ने मनरेगा में पारदर्शिता और डायरेक्ट ट्रांसफर सुनिश्चित किया, लेकिन समय पर मजदूरी में क्रांतिकारी सुधार नहीं ला सका। रीवा क्षेत्र में व्यय वृद्धि सकारात्मक है, पर विलंब बने हैं। निजी क्षेत्र की कमाई बढ़ी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है।यह अध्ययन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के भुगतान सुधारों – विशेष रूप से बायोमेट्रिक और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली** (Aadhaar Based Payment System - ABPS) – **के**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, March 2026
Impact Factor: 8.2

प्रभाव का विश्लेषण करता है। मुख्य फोकस समय पर मजदूरी (timely wages) और निजी क्षेत्र की कमाई (private sector earnings) पर प्रभाव रहा है।

परिणाम दर्शाते हैं कि ABPS ने योजना में पारदर्शिता और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को मजबूत किया है। PIB (मार्च 2025) के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर आधार सीडिंग 99.49% पहुंच चुकी है, और मध्य प्रदेश में औसत मजदूरी दर ₹228.77 (2024-25) से बढ़कर 2025-26 में और सुधार दिखा है। रीवा जिले में 2024-25 का कुल व्यय ₹10,394.33 लाख रहा, जिसमें अकुशल मजदूरी का हिस्सा प्रमुख था। ABPS के कारण लीकेज कम हुआ और भुगतान प्रक्रिया अधिक ट्रैकेबल बनी। हालांकि, समय पर मजदूरी में क्रांतिकारी सुधार नहीं आया। LibTech India और The Indian Journal of Labour Economics (2025) की बड़ी स्केल स्टडी (31.36 मिलियन ट्रांजेक्शंस, 10 राज्यों से) स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ABPS और सामान्य बैंक खाता-आधारित भुगतान में समय पर मजदूरी (15 दिनों के अंदर) या रिजेक्शन रेट में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। ABPS में 39% भुगतान 7 दिनों में हुए, जबकि सामान्य में 36% – अंतर नगण्य। The Hindu (जनवरी 2025) की रिपोर्ट भी यही पुष्टि करती है: "No empirical evidence that Aadhaar-based payment for MGNREGA workers is significantly better."

रीवा जिले में nrega.nic.in की Delayed Payment Detail Reports (2025-2026) से पता चलता है कि कई पंचायतों (जैसे Agadal, Rithi आदि) में अभी भी विलंबित भुगतान बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2024-25 में ₹974.38 करोड़ मजदूरी अनपेड रही (IndiaSpend, मार्च 2025), और केंद्र सरकार द्वारा ₹39 करोड़ डिले कम्पेंसेशन बकाया है। मुख्य कारण फंड रिलीज की देरी, बजट कटौती और ABPS की तकनीकी अड़चनें (जैसे आधार e-KYC फेलियर, 27% वर्कर्स इनएलीजिबल – LibTech India) हैं। रीवा जैसे पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या और गंभीर है, जहां मजदूरों की आजीविका सीधे प्रभावित होती है।

IJARSCT

ISSN: 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

Volume 6, Issue 3, March 2026

Impact Factor: 8.2

सुझाव:

- फंड रिलीज समयबद्ध करें।
- रीवा में ब्लॉक स्तर पर लोकल ग्रिवांस सिस्टम।
- प्राथमिक सर्वे कर प्रभाव मापें।
- ABPS को NMMS ऐप से जोड़कर और मजबूत करें।
- यह अध्ययन दर्शाता है कि तकनीकी सुधार के साथ फंडिंग और प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं।

भविष्य में VB-GRAM G जैसी योजनाओं के साथ तुलना की जा सकती है।

संदर्भ (References)

[1]. Press Information Bureau (PIB). (2025, March 18). Aadhaar Based Payment Systems under Mahatma Gandhi NREGA. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112199

[2]. The Hindu. (2025, January 23). New MGNREGS wage payment system not significantly better: study. https://www.thehindu.com/news/national/no-empirical-evidence-that-aadhaar-based-payment-for-mnrega-workers-is-significantly-better-study/article69132596.ece

[3]. nrega.nic.in. (2025). Rewa District Expenditure Report 2024-25. https://mnregaweb4.nic.in/... (Total Exp. ₹10,394.33 लाख)

[4]. Sukhtankar, S. (2016). India's National Rural Employment Guarantee Scheme.

[5]. Patwardhan, S. & Tasciotti, L. (2022). The effect of MGNREGA on outstanding debts. Journal of Development Effectiveness.

[6]. Pandey, D. (2018). Impact of MGNREGA on Rural Wages. University of Minnesota.

[7]. Annual Master Circular 2024-25, Ministry of Rural Development.

[8]. Lib Tech India Study (2025) – Indian Journal of Labour Economics.

[9]. NREGA MIS Reports, Madhya Pradesh & Rewa District (2024-25).

[10]. Additional: 3ie Working Paper on MGNREGA Effectiveness (2016